ई-न्यूज

24 न्यूज अपडेट

WebSite.: https://24newsupdate.in

उदयपुर, शुक्रवार 19 दिसम्बर 2025

Mail Id :desk24newsupdate@gmail.com

वर्ष 2 अंक 229

सट्टेबाजी ऐप प्रमोशन मामला: ED का बड़ा एक्शन, युवराज-सोनू सूद सहित कई नामी सेलेब्स की संपत्तियां जब्त

24 न्यूज अपडेट

नई दिल्ली। अवैध सट्टेबाजी ऐप के प्रचार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह, बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद, अभिनेत्री नेहा शर्मा सहित कई नामी हस्तियों की संपत्तियां जब्त कर ली हैं। एजेंसी की यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस मामले में मॉडल-अभिनेत्री उर्वशी रौतेला की मां, बंगाली अभिनेता अंकुश हाजरा, पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा और पूर्व तृणमूल कांग्रेस सांसद मिमी चक्रवर्ती की संपत्तियों को भी ED ने कुर्क किया है। जब्त की गई कुल संपत्तियों की अनुमानित कीमत 1,000 करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक, सोनू सूद की करीब 1 करोड़ रुपये, युवराज सिंह की 2.5 करोड़ रुपये, नेहा शर्मा की 1.26 करोड़ रुपये, मिमी चक्रवर्ती की 59 लाख रुपये, रॉबिन उथप्पा की 8.26 लाख रुपये, अंकुश हाजरा की 47 लाख रुपये और उर्वशी रौतेला की मां की लगभग 2.02 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की गई हैं। ED का आरोप है कि इन सभी सेलेब्स ने 1xBet नामक अवैध सट्टेबाजी ऐप का प्रचार किया और इसके बदले मिली रकम को मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए प्राप्त किया गया। एजेंसी ने अंतरिम आदेश जारी करने के बाद यह कार्रवाई की है। इससे पहले भी इस मामले में संबंधित सेलेब्स से पूछताछ की जा चुकी है। बीते 24 सितंबर को ED ने अभिनेता सोनू सूद से दिल्ली स्थित कार्यालय में करीब सात घंटे तक पूछताछ कर PMLA के तहत बयान दर्ज किया था। गौरतलब है कि इससे पहले ED ने इसी केस में पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन और सुरेश रैना की भी 11.14 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की थीं।

1xBet पर पहले से प्रतिबंध

1xBet साइप्रस स्थित एक ऑनलाइन बेटिंग कंपनी है, जिसकी स्थापना वर्ष 2007 में हुई थी। यह प्लेटफॉर्म दुनिया भर के खेल आयोजनों पर सट्टा लगाने की सुविधा देता है और खुद को वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त बताता है। हालांकि भारत में यह ऐप और वेबसाइट प्रतिबंधित हैं। जांच एजेंसियों का कहना है कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए बड़े पैमाने पर अवैध लेनदेन, टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग की गई। भारत सरकार ने ऑनलाइन बेटिंग और सट्टेबाजी ऐप्स पर सख्त रुख अपनाते हुए हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के तहत ऐसे प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया है। सरकार का कहना है कि इन ऐप्स से आम लोगों को भारी मानसिक और आर्थिक नुकसान हो रहा है। संसद में दी गई जानकारी के अनुसार, करोड़ों लोग ऑनलाइन बेटिंग की लत से प्रभावित हुए हैं और इससे हजारों करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ है।

राजस्थान बोर्ड ने 10वीं-12वीं परीक्षा का टाइम टेबल किया जारी, 19.86 लाख विद्यार्थी होंगे शामिल

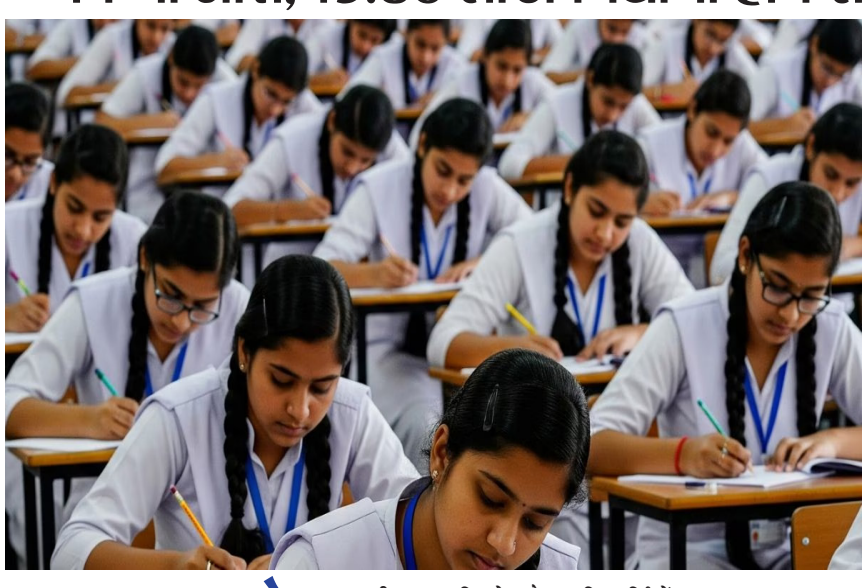

24 न्यूज अपडेट

अजमेर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया है। बोर्ड के अनुसार 10वीं की परीक्षाएं 12 फरवरी से 28 फरवरी तक आयोजित होंगी, जो कुल 17 दिन चलेंगी। वहीं 12वीं की परीक्षाएं 12 फरवरी से शुरू होकर 11 मार्च तक संपन्न होंगी, जिनकी अवधि 28 दिन निर्धारित की गई है। बोर्ड सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि परीक्षा अवधि के दौरान विद्यार्थियों को कुल 6 दिन की छुट्टी मिलेगी। इनमें चार रविवार तथा होली और धुलंडी के अवकाश शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इस वर्ष कुल 19 लाख 86 हजार 422 विद्यार्थी बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होंगे। इनमें कक्षा 10वीं के 10 लाख 68 हजार 610 विद्यार्थी, कक्षा 12वीं के 9 लाख 05 हजार 572 विद्यार्थी, वरिष्ठ उपाध्याय के 4 हजार 123 तथा प्रवेशिका के 7 हजार 817 विद्यार्थी शामिल हैं। परीक्षाओं के संचालन के लिए प्रदेशभर में 6 हजार 193 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, नकल पर रहेगी कड़ी नजर बोर्ड सचिव ने बताया कि परीक्षा की गोपनीयता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। प्रश्न पत्रों को पुलिस थानों और चौकियों में सुरक्षित रखा जाएगा। परीक्षा केंद्रों पर नकल रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के करीब 15 जिलों को संवेदनशील और अति संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है, जहां विशेष तौर पर वीडियोग्राफी कराई जाएगी। इन जिलों में लगभग 51 परीक्षा केंद्र अति संवेदनशील घोषित किए गए हैं। इसके साथ ही उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन इस बार तेजी से किया जाएगा, ताकि परिणाम समय पर घोषित किए जा सकें।

उदयलाल डांगी और प्रतापलाल भील बने MLSU बॉम मेम्बर

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय (सुविवि) के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट (BOM) में लंबे समय बाद राजनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति की गई है। राज्य सरकार ने राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष की सहमति के बाद यह नियुक्तियां की हैं, जिससे विश्वविद्यालय के शीर्ष प्रशासनिक निकाय में राजनीतिक प्रतिनिधित्व बहाल हो गया है। उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, विधानसभा क्षेत्र वल्लभनगर (उदयपुर) से विधायक श्री उदयलाल डांगी तथा गोगुंदा (उदयपुर) से विधायक श्री प्रतापलाल भील को सुविवि बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का सदस्य मनोनीत किया गया है। यह मनोनयन मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय अधिनियम, 1962 की धारा 19(1)(III)(VI) के तहत किया गया है। दोनों विधायकों की यह नियुक्ति एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा विधानसभा सदस्यता की अवधि समाप्त होने तक, जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगी। आदेश के अनुसार यह मनोनयन तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा और इसकी अवधि 6 जून 2026 तक निर्धारित की गई है। इस संबंध में आदेश संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा विभाग डॉ. मुकेश कुमार शर्मा द्वारा जारी किया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन और शैक्षणिक हलकों में इन नियुक्तियों को लंबे अंतराल के बाद हुआ महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे विश्वविद्यालय की नीतियों और विकास कार्यों में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित होगी।

नेक्स्नोज़ निर्माण एक्सपो एवं नॉलेज सेशन का भव्य शुभारंभ, देशभर के आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स और इंटीरियर डिज़ाइनर्स शामिल

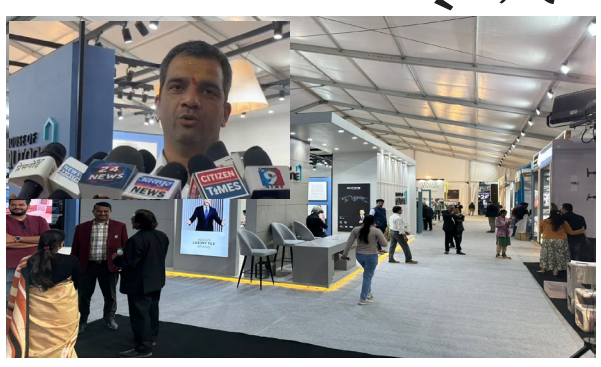

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। निर्माण एवं इंटीरियर डेकोरेशन क्षेत्र से जुड़ी राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित प्रदर्शनी 'नेक्स्नोज़ निर्माण एक्सपो' के आठवें संस्करण का भव्य शुभारंभ शुक्रवार को शुभ केसर गार्डन में हुआ। तीन दिवसीय यह एक्सपो 19 से 21 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देशभर से उद्योग जगत के विशेषज्ञ, प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स भाग ले रहे हैं। आयोजक कंचन शर्मा ने बताया कि इस एक्सपो में भवन निर्माण एवं इंटीरियर सजावट से संबंधित नवीनतम मटीरियल, अत्याधुनिक तकनीक और नवाचारों को एक ही मंच पर प्रस्तुत किया गया है। पहले ही दिन उदयपुर संभाग सहित आसपास के क्षेत्रों से सैकड़ों विज़िटर्स ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया।

नॉलेज सेशन में उभरे भविष्य के ट्रेंड्स

एक्सपो के साथ आयोजित नॉलेज सेशन में उदयपुर सहित देशभर से करीब 100 आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स एवं इंटीरियर डिज़ाइनर्स ने सहभागिता की। देश के विभिन्न हिस्सों से आए विशेषज्ञों ने अपने अनुभव साझा करते हुए वैश्विक स्तर पर हो रहे नवाचारों और बदलते उपभोक्ता रुझानों पर प्रकाश डाला। विशेषज्ञों ने कहा कि आज का युवा वर्ग अपने घर और प्रतिष्ठानों को विशिष्ट पहचान देना चाहता है, ऐसे में वही प्रोडक्ट और डिज़ाइन टिकाऊ साबित होंगे जो समय के साथ स्वयं को अपडेट करें। व्यवसायियों को बदलती सोच के अनुरूप नवाचार को अपनाना होगा। इस नॉलेज सेशन में इस क्षेत्र से जुड़े स्टूडेंट्स ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया और प्रश्नों के माध्यम से अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त किया।

उद्यमियों के लिए विशेष सेमिनार

शाम को आयोजित विशेष सेमिनार में उदयपुर के प्रमुख उद्यमी एवं लघु उद्योग भारती के सदस्य शामिल हुए। इस अवसर पर वंडर सीमेंट से परमानंद पाटीदार तथा निखारा मार्बल से प्रभास राजगडिया विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। श्री राजगढ़िया ने कहा कि यह प्रदर्शनी उदयपुर के उद्यमियों और आमजन के लिए एक मील का पत्थर सिद्ध होगी, क्योंकि यहां निर्माण और सजावट से जुड़ी हर आवश्यकता एक ही स्थान पर उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि उदयपुर मार्बल नगरी है और इस एक्सपो में मार्बल की विभिन्न श्रेणियों का प्रभावशाली प्रदर्शन किया गया है।

स्थानीय उद्योग और परंपरा को समर्पित आयोजन

सेमिनार में स्थानीय निर्माण उद्योग से जुड़े विषयों पर भी सार्थक चर्चा हुई और यह विचार किया गया कि किस प्रकार युवा वर्ग को इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए। प्रदर्शनी में भगवान विश्वकर्मा की विशेष झांकी भी आकर्षण का केंद्र रही। संपूर्ण आयोजन हिन्दू धर्म में निर्माण के देवता भगवान विश्वकर्मा को समर्पित है। आयोजक कमलेश शर्मा ने बताया कि इस आयोजन को हर वर्ष और अधिक सशक्त बनाते हुए राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए वे निरंतर प्रयासरत हैं। यह आयोजन उनके अपने शहर उदयपुर और अपने पेशे के प्रति समर्पण का प्रतीक है। स्थानीय पेशेवर मित्रों और सहयोगी कंपनियों के सहयोग से यह एक्सपो हर वर्ष नई ऊंचाइयों को छू रहा है।

RRP सेमीकंडक्टर पूरी दुनिया में सबसे तेज उछाल वाला शेयर: 15 रुपए का शेयर 20 महीने में 11,095 का हुआ; ट्रेडिंग पर पाबंदी

24 न्यूज अपडेट

भारतीय शेयर बाजार की एक अजीब घटना ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। RRP सेमीकंडक्टर के शेयर सिर्फ 20 महीने में 793 गुना यानी 79,000% से ज्यादा चढ़ चुके हैं।

इतना ज्यादा रिटर्न देने वाली यह दुनिया की एकमात्र कंपनी है। 2 अप्रैल 2024 में RRP का 15 रुपए का ये शेयर इस साल नवंबर में 11,902 रुपए तक गया, जो इसका 52 वीक हाई भी था।

इसलिए मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने शेयरों में इस उछाल की जांच शुरू कर दी है। BSE ने भी इस कंपनी को सख्त निगरानी के दायरे में डाला है।

इस शेयर को अब 1% प्राइस बैंड के साथ हफ्ते में सिर्फ एक दिन ट्रेडिंग की अनुमति दी गई है। ये शेयर उच्चतम स्तर से करीब 6% गिर चुका है। BSE के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक, कंपनी के शेयरों में हर हफ्ते औसतन केवल 19 शेयरों में ट्रेडिंग हो रही थी।

सितंबर 2024 में RRP की नई यूनिट इलेक्ट्रॉनिक्स के उद्घाटन समारोह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और सचिन तेंदुलकर मौजूद थे। सोशल मीडिया पर माहौल बना कि तेंदुलकर ने कंपनी में बड़ा निवेश किया है और इसे महाराष्ट्र सरकार से प्लांट लगाने के लिए जमीन मिली है।

सेंसेक्स 447 अंक चढ़कर 84,929 पर बंद हुआ: निफ्टी भी 150 अंक चढ़ा; ऑटो, रियल्टी और हेल्थकेयर सेक्टर सबसे ज्यादा चढ़े

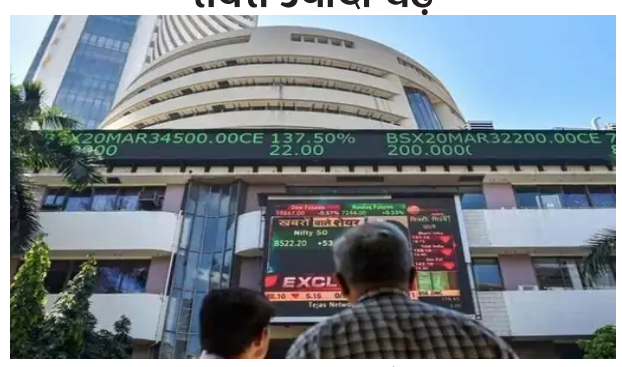

24 न्यूज अपडेट

लगातार चार दिन की गिरावट के बाद शेयर बाजार में आज यानी शुक्रवार 19 दिसंबर तेजी रही। सेंसेक्स 447 अंक चढ़कर 84,929 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 150 अंक की तेजी रही, ये 25,966 के स्तर पर बंद हुआ।

सेंसेक्स के सभी 30 शेयरों में से 26 में तेजी और 4 में गिरावट रही। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, पावर ग्रिड और BEL के शेयरों में 2% तक की तेजी रही। निफ्टी के 50 शेयरों में से 41 में तेजी और 9 में गिरावट रही। NSE के सभी सेक्टर्स ऊपर हैं। ऑटो, रियल्टी और हेल्थकेयर में सबसे ज्यादा तेजी रही।

चांदी 2 लाख के ऊपर बरकरार, आज 784 सस्ती हुई: सोने की कीमत में 80 रुपए की गिरावट, 1,32,394/10G पहुंचा

24 न्यूज अपडेट

सोने और चांदी की कीमत में आज (19 दिसंबर) मामूली गिरावट देखी जा रही है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, 10 ग्राम सोने की कीमत 80 रुपए घटकर 1,32,394 हो गई है।

गुरुवार को इसकी कीमत 1,32,474 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। इससे पहले 15 दिसंबर को सोने की कीमत 1,33,249 रुपए के अपने अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर थी।

वहीं, चांदी के दाम आज 784 रुपए घटकर 2,00,336 प्रति किलो पर आ गए हैं। इससे पहले गुरुवार को चांदी 2,01,120/KG के ऑल टाइम हाई पर थी।

संपादकीय : रोजगार की राह

देश के ग्रामीण इलाकों में ज्यादातर आबादी के लिए रोजी-रोटी का इंतजाम एक बड़ी चुनौती रही है। लंबे समय तक इस समस्या के बने रहने का नतीजा यह हुआ कि विकास एक तरह से विभाजित रहा और एक बड़ा तबका मुख्यधारा मे शामिल होने की कोशिशों से भी वंचित रहा। मगर जब से गारंटी के रूप में ग्रामीण इलाकों में रोजगार मुहैया कराने की पहल हुई है, उसके बाद से एक बड़ा फर्क दर्ज किया गया। करीब बीस वर्ष पहले महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून यानी मनरेगा लागू हुआ, तो उसके तहत वर्ष में सौ दिन काम की व्यवस्था से गांव-देहात में रहने वाले परिवारों के सशक्तीकरण में उल्लेखनीय मदद मिली। मनरेगा की अहमियत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि कई बार इसे दुनिया भर में एक सीखने लायक कार्यक्रम के तौर पर भी देखा गया। अब केंद्र सरकार ने मनरेगा का रूप बदल कर उसका नाम 'विकसित भारत- रोजगार गारंटी व आजीविका मिशन (ग्रामीण) ' यानी 'बीवी - जी राम जी' रखा है और उसमें अब कुछ नए प्रावधान किए गए हैं। इससे संबंधित विधेयक गुरुवार को लोकसभा में पारित हो गया । गौरतलब है कि नई प्रस्तावित व्यवस्था मनरेगा का ही नया स्वरूप होगी, जिसमें ग्रामीण परिवार को सौ दिन के बजाय एक सौ पच्चीस दिनों के रोजगार की गारंटी की बात की गई है। इसके अलावा, खर्च वहन करने, पारिश्रमिक भुगतान और खेती के दिनों के संदर्भ में नए प्रावधानों की वजह से इस योजना के किसानों और मजदूरों, दोनों के लिए काफी फायदेमंद साबित होने की उम्मीद की जा रही है। मनरेगा के तहत जिन लोगों को काम मिलता है, उनकी मजदूरी का लगभग पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाती रही है, जबकि सामान आदि का खर्च एक निश्चित अनुपात में राज्य सरकारें उठाती है। अब कुछ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को छोड़ कर 'बीवी - जी राम जी' के तहत होने वाले कुल खर्च का साठ फीसद केंद्र सरकार वहन करेगी और चालीस फीसद राज्य सरकारें उठाएंगी। इस योजना के अंतर्गत खेतों में बुआई और कटाई के मौसम में साठ दिनों के दौरान मजदूरों को काम नहीं मिल सकेगा, ताकि खेती-किसानी के काम के लिए मजदूरों की कमी न हो। इसके अलावा, इस काम में भ्रष्टाचार पर लगाम के लिए मजदूरी के भुगतान में बायोमेट्रिक और अन्य आधुनिक तकनीक की मदद ली जाएगी। जाहिर है, बदलावों के बाद अगर रोजगार गारंटी की व्यवस्था ग्रामीण इलाकों के मजदूरों के लिए सहायक सिद्ध हुई, तो बेशक इसे एक सकारात्मक कदम माना जाएगा। देश की ग्रामीण आबादी के हित में प्रथम दृष्टया यह योजना एक बेहतर पहल लगती है, लेकिन इस संदर्भ में विपक्षी दलों की ओर से कई आशंकाएं भी जताई गई हैं। अगर ग्रामीण इलाकों में काम करने की जगह तय करने से लेकर अन्य मामलों में यह योजना केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित और उसकी शर्तों पर आधारित होगी, तो खर्च का जिम्मा राज्यों पर आएगा। ऐसे में इसके नतीजे घोषित दावों के मुकाबले उलट भी आ सकते हैं और इसका काम के अधिकार पर विपरीत असर पड़ सकता है। ग्रामीण इलाकों में रोजगार गारंटी लागू होने के बाद से मनरेगा की अहमियत छिपी नहीं रही है। खासतौर पर कोरोना महामारी के दौरान जब देश भर में गरीब तबकों के लोग भयावह अभाव से जूझ रहे थे, तब मनरेगा उनके लिए जीवन-रेखा साबित हुआ। ऐसे में यह देखने की बात होगी कि नए स्वरूप में ग्रमीण इलाकों के गरीब तबकों के लिए रोजगार गारंटी की नई व्यवस्था कितनी सहायक साबित होगी।

खामी की परतें

चुनावों के दौरान अक्सर आनन-फानन में घोषणाएं की जाती हैं। ऐसी योजनाओं के अमल के दौरान लापरवाही की आशंका बनी रहती है। कई बार यह चूक का नतीजा होती है तो कभी जानबूझ कर ऐसा करने के आरोप लगते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत एक करोड़ चालीस लाख महिलाओं के खाते में दस- दस हजार रुपए भेजे गए थे। इसका उद्देश्य जो भी रहा हो, लेकिन हड़बड़ी में घोषित इस योजना को अमल में लाने के क्रम में कई पुरुषों के खाते में भी राशि भेज दी गई। सवाल है कि अगर यह सिर्फ चूक थी, तो इसके लिए क्या खुद सरकारी तंत्र जिम्मेदार नहीं है! खबरों के मुताबिक, बिहार के दरभंगा जिले के जाले विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कई मामले सामने आए। सफाई के तौर पर कहा जा रहा है कि 'तकनीकी खामी की वजह से ऐसा हुआ और अब उसकी वसूली की खबरें हैं। मगर चुनाव से ऐन पहले इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं के खाते में राशि अंतरित करते समय संबंधित अधिकारियों ने पर्याप्त सावधानी क्यों नहीं बरती ? हालत यह है कि राशि भेजने के क्रम में संबंधित बैंकों के अधिकारियों तक ने इस पर ध्यान नहीं दिया । गौरतलब है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत लाखों महिलाओं के खाते में द्रुत गति से राशि डाले जाने के दौरान कई सवाल उठे थे, जिनका बेशक जवाब न मिला हो, पर जागरूक नागरिकों के लिए यह समझना कोई मुश्किल नहीं था । ऐसे आरोप स्वाभाविक ही थे कि सरकार ने महिला मतदाताओं और उनके जरिए एक बड़े तबके का वोट हासिल करने के मकसद से उनके खाते में राशि भेजी । तब सरकार और राजग ने इसे महिलाओं को रोजगार शुरू करने में सहायता के तौर पर पेश किया था। मगर अब कई पुरुषों के खाते में राशि भेजे जाने और अब उसकी वसूली की कवायद के बाद एक तरह से उन आरोपों को बल मिला है कि सरकार का मकसद जितना सहायता देना था, उससे ज्यादा उसने इसे वोट लेने का जरिया बनाया। अगर यह केवल लापरवाही और हड़बड़ी में की गई गड़बड़ी का भी मामला है, तो इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को होने वाले नुकसान का अंदाजा लगाया जा सकता है।

अरविंद सिंह मेवाड़ की वसीयत को बेटी पद्मजा कुमारी ने दी चुनौती, मामला अब दिल्ली हाईकोर्ट में

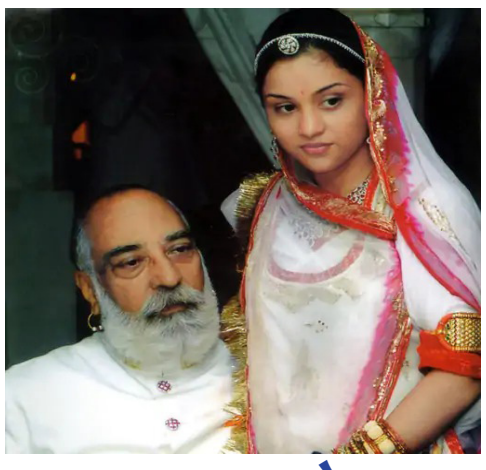

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। उदयपुर के पूर्व राजपरिवार से जुड़ा दशकों पुराना संपत्ति विवाद अब एक बार फिर न्यायपालिका के उच्च स्तर तक पहुंच गया है। पूर्व महाराणा अरविंद सिंह मेवाड़ की वसीयत को चुनौती देते हुए उनकी पुत्री पद्मजा कुमारी परमार द्वारा दायर याचिका पर अब दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। यह विवाद अरविंद सिंह मेवाड़ के पुत्र लक्ष्यराज सिंह मेवाड़—जो वर्तमान में एचआरएच ग्रुप ऑफ होटल्स के चेयरमैन एवं मेवाड़ परिवार के उत्तराधिकारी माने जाते हैं—और उनकी बहन पद्मजा कुमारी के बीच है। विवाद का केंद्र बिंदु सिटी पैलेस, एचआरएच होटल्स ग्रुप सहित अन्य ऐतिहासिक व बहुमूल्य संपत्तियां हैं।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दिल्ली हाईकोर्ट में होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने अदालत को अवगत कराया कि मेवाड़ परिवार के विभिन्न सदस्यों के बीच उत्तराधिकार और वसीयत की वैधता को लेकर अलग-अलग न्यायालयों में मामले लंबित थे, जिससे न्यायिक प्रक्रिया बिखर रही थी। इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी लंबित मामलों को एक मंच पर लाने के उद्देश्य से उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि दोनों पक्षों के बीच अन्य कोई मामला लंबित हो, तो उसे भी दिल्ली हाईकोर्ट स्थानांतरित कराने हेतु आवेदन किया जा सकता है।

दोनों पक्षों की अलग-अलग याचिकाएं

लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने मुंबई हाईकोर्ट में लंबित मामलों को राजस्थान हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की थी। वहीं पद्मजा कुमारी परमार ने जोधपुर बेंच राजस्थान हाईकोर्ट में चल रहे मामलों को बॉम्बे हाईकोर्ट भेजने का आग्रह किया था। इन परस्पर विरोधी मांगों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने न्यायहित में दिल्ली हाईकोर्ट को उपयुक्त मंच मानते हुए अंतिम आदेश पारित किया।

दशकों पुराना है मेवाड़ राजपरिवार का संपत्ति विवाद

मेवाड़ पूर्व राजपरिवार में संपत्ति को लेकर विवाद की जड़ें वर्ष 1983 से जुड़ी हैं, जब महाराणा भगवत सिंह मेवाड़ ने पारिवारिक संपत्तियों को बेचने और लीज पर देने का निर्णय लिया। इस निर्णय का उनके बड़े पुत्र महेंद्र सिंह मेवाड़ ने विरोध किया और न्यायालय की शरण ली। इसके बाद पारिवारिक मतभेद गहराते चले गए। 1984 में भगवत सिंह मेवाड़ के निधन के पश्चात यह विवाद और जटिल हो गया। लगभग 37 वर्षों तक चली कानूनी लड़ाई के बाद वर्ष 2020 में उदयपुर जिला अदालत ने संपत्तियों के बंटवारे का आदेश पारित किया। हालांकि, इसके बावजूद विवाद पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ और अब एक बार फिर यह मामला उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। अब यह मामला ऐतिहासिक विरासत, ट्रस्ट, वसीयत की वैधता और न्यायिक अधिकार क्षेत्र से जुड़े गंभीर संवैधानिक प्रश्नों को भी जन्म देता है। दिल्ली हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई से यह तय होगा कि मेवाड़ राजपरिवार के इस लंबे विवाद को न्यायिक रूप से किस दिशा में अंतिम समाधान मिलता है।

डूंगरपुर पुलिस बनी बाराती, शहनाइयों के बीच दबोच लिया 160 करोड़ की ठगी का मास्टर माइंड

24 न्यूज अपडेट

डूंगरपुर। डूंगरपुर पुलिस ने साइबर ठगी की दुनिया में ऐसा वार किया है, जिसकी गूंज देश ही नहीं, विदेशों तक सुनाई दे रही है। राजस्थान के डूंगरपुर से शुरू हुई जांच ने दुबई और जॉर्जिया तक फैले 160 करोड़ रुपये के ऑनलाइन ठगी रैकेट का पर्दाफाश कर दिया। इस हाई-प्रोफाइल ऑपरेशन की सबसे चौंकाने वाली तस्वीर गुजरात के दाहोद से सामने आई, जहां पुलिसकर्मी बाराती बनकर शादी में घुसे और शातिर ठग को शहनाइयों के बीच दबोच लिया। डूंगरपुर साइबर सेल की स्पेशल टीम के पांच पुलिसकर्मी शेरवानी, सिर पर साफा और पगड़ी पहनकर गुजरात के दाहोद जिले के लिमड़ी गांव पहुंचे। मौका था एक शादी समारोह का। इसी बारात में शामिल था 160 करोड़ की ठगी की साजिश का अहम किरदार कौशल कुम्हार। जैसे ही उसकी पहचान पुख्ता हुई, पुलिस ने उसे मौके पर ही हिरासत में ले लिया। अचानक हुई इस कार्रवाई से बारातियों के साथ खुद आरोपी के भी होश उड़ गए।

पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने बताया कि कौशल कुम्हार डूंगरपुर के एक निजी बैंक में कार्यरत था और अपने पद का दुरुपयोग कर फर्जी बैंक खातों का जाल बिछा रहा था। उसने अपने साथी इलेश पटेल उर्फ निलेश कलाल के साथ मिलकर गरीब मजदूरों, छात्रों और बेरोजगार युवाओं को सरकारी योजनाओं, पैन कार्ड और छात्रवृत्ति का झांसा देकर 450 से ज्यादा फर्जी बैंक खाते खुलवाए। इन खातों की चेकबुक, एटीएम और किट खुद अपने कब्जे में रखी गई। जांच में सामने आया कि इन खातों का इस्तेमाल दुबई और जॉर्जिया में बैठे अंतरराष्ट्रीय ठग कर रहे थे। घनश्याम कलाल, वरुण कलाल और उपेंद्र कलाल दुबई से, जबकि डेनी उर्फ डैनी नटवरलाल जॉर्जिया से पूरे नेटवर्क को ऑपरेट कर रहे थे। शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसी और ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स के जरिए देशभर के लोगों से 160 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की गई। शादी के बाद विदेश भागने की फिराक में था कौशल पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि कौशल कुम्हार शादी समारोह के बाद विदेश भागने की तैयारी में था, ठीक अपने अन्य साथियों की तरह। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने उसके करीबी साथी इलेश पटेल उर्फ निलेश कलाल को सागवाड़ा स्थित उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। दो अलग-अलग मामलों की जांच ने खोली पोल साइबर सेल की जांच दो मामलों से शुरू हुई थी। बथड़ी निवासी लालशंकर रोत और सागवाड़ा निवासी अशोक डांगी की शिकायतों में सामने आया कि उनके खातों में लाखों रुपये का संदिग्ध लेन-देन हुआ। जांच की कड़ियां जुड़ती गईं और पूरा अंतरराष्ट्रीय ठगी नेटवर्क उजागर हो गया। एसपी मनीष कुमार ने इस साहसिक और रणनीतिक कार्रवाई को अंजाम देने वाली साइबर सेल टीम को सम्मानित किया है। साथ ही पुलिस मुख्यालय के माध्यम से दुबई और जॉर्जिया में बैठे आरोपियों को पकड़ने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं।

कुएं में डूबे मासूम को निकालने में जुटी नागरिक सुरक्षा टीम, एक घंटे बाद 70 फीट गहराई से शव बरामद

24 न्यूज अपडेट

आज दोपहर करीब तीन बजे पुलिस थाना डबोक से सूचना मिली कि औरवाड़िया–गुडली रीको इंडस्ट्रियल एरिया क्षेत्र के एक गांव में पानी पीने गया एक मासूम बच्चा कुएं में गिरकर डूब गया है। सूचना मिलते ही राजस्थान नागरिक सुरक्षा विभाग उदयपुर की टीम तुरंत मौके के लिए रवाना हुई। टीम के मौके पर पहुंचने के बाद करीब एक घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन में 70 फीट गहरे कुएं से बच्चे का शव बाहर निकाला गया। रेस्क्यू के बाद शव को पुलिस थाना डबोक के सुपुर्द किया गया। इस अभियान में वाहन चालक प्रकाश राठौड़, गोताखोर विपुल चौधरी, भवानी शंकर, नरेश चौधरी, विजय नकवाल और बोट ऑपरेटर कैलाश मेनारिया शामिल रहे। पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में गोताखोर विपुल चौधरी की विशेष भूमिका रही। मृतक बच्चे की पहचान गोविंद वागरीया पुत्र भेरुलाल वागरीया, उम्र करीब 9 वर्ष के रूप में हुई है। घटना के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है।

एम.डी.एस. स्कूल के हिमांशु जनवा का राजस्थान अंडर-16 क्रिकेट टीम के लिए चयन

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर की उभरती हुई क्रिकेट प्रतिभा एम.डी.एस. स्कूल के छात्र हिमांशु जनवा का चयन राजस्थान अंडर-16 क्रिकेट टीम में होने से विद्यालय, परिवार एवं खेल जगत में हर्ष का वातावरण है। यह चयन हिमांशु की निरंतर मेहनत, अनुशासन एवं उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन का परिणाम है। एम.डी.एस के स्पोर्ट्स प्रभारी श्री प्रदीप त्रिवेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि हिमांशु जनवा एक प्रतिभाशाली ऑलराउंडर हैं, जो अपनी लेफ्ट-आर्म स्पिन गेंदबाज़ी के साथ-साथ मध्यक्रम में सशक्त बल्लेबाज़ी के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से सभी का ध्यान आकर्षित किया है। हिमांशु वर्तमान में एम.डी.एस. स्कूल की कक्षा 10वीं के नियमित छात्र हैं तथा पढ़ाई के साथ-साथ खेलों में भी निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। वे विनय क्रिकेट क्लब द्वारा संचालित क्रिकेट अकादमी में नियमित अभ्यास करते हैं, जहाँ उन्हें पूर्व रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी श्री चंद्रपाल सिंह चुंडावत का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। अनुभवी कोच के निर्देशन में हिमांशु की तकनीक और खेल कौशल में निरंतर निखार आया है। उल्लेखनीय है कि हिमांशु इससे पूर्व राजस्थान अंडर-14 क्रिकेट टीम का भी सफलतापूर्वक प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। हिमांशु के इस उल्लेखनीय चयन पर विद्यालय के निदेशक डॉ. शैलेन्द्र सोमानी, समस्त शिक्षकगण, विद्यालय परिवार एवं खेल प्रेमियों ने हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें उज्ज्वल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ प्रदान की तथा विश्वास व्यक्त किया कि वे भविष्य में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर विद्यालय एवं उदयपुर जिले का नाम रोशन करेंगे।

38वीं डांगी समाज खेलकूद प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा गांव पुलां

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। डांगी सेवा संस्थान खेल संघ उदयपुर की आवश्यक बैठक गांव पूला में खेल संघ अध्यक्ष रामलाल डांगी पुला की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि 38वीं डांगी समाज की खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन गांव पूला द्वारा किया जाएगा इसको लेकर शनिवार को बालाजी स्पोर्ट्स क्लब पुला मे प्रातः 10:00 बजे सभी टीमों की टाई डाली जाएगी । खेल संघ की बैठक में संस्थान उपाध्यक्ष केशु लाल डांगी, सचिव रमेश डांगी भुवाणा, कोषाध्यक्ष दुदाराम डांगी, दिनेश पटेल एडवोकेट, धर्म नारायण डांगी सापेटिया, नारायण गुड्डू डांगी भूवाना, बाबूलाल पटेल सापेटीया शंभू डांगी मानपूरा, सीताराम डांगी शोभागपुरा, पुष्कर डांगी पूला, प्रवीण डांगी पुला के साथ ही नवयुवक मंडल पुला के सभी युवा कार्यकर्ता रतन डांगी, मनोहर डांगी, दुर्गेश डांगी कपिल डांगी एवं ग्रामवासी मौजूद थे।

मोरन नदी पर पुलिया निर्माण का किया भूमि पूजन, दस करोड़ की लागत से मोरन नदी पर पुलिया निर्माण का भूमि पूजन

24 न्यूज अपडेट

सागवाड़ा (जयदीप जोशी)। नगर के निकटवर्ती वरदा से किशनपुरा को जोड़ने वाली सड़क पर दस करोड़ की लागत से बनने वाली पुलिया निर्माण का शुक्रवार को भूमि पूजन किया गया। सार्वजनिक निर्माण विभाग खंड सागवाड़ा द्वारा वरदा से किशनपुरा को जोड़ने वाली सड़क पर मोरन नदी पर प्रस्तावित पुलिया निर्माण कार्य का जनप्रतिनिधियों एवं विभागीय अधिकारियों ने विधिवत पूजा-अर्चना कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। पुलिया के निर्माण से क्षेत्र के ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा मिलेगी तथा बरसात के मौसम में होने वाली परेशानी से राहत मिलेगी। यह परियोजना क्षेत्र के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण एवं ग्रामीणजन उपस्थित रहे। सभी ने इस विकास कार्य के लिए शासन व प्रशासन का आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री शनिवार को डबोक आकर बांसवाड़ा जाएंगे

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर, 19 दिसम्बर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा शनिवार को उदयपुर के प्रवास पर रहेंगे। जिला कलक्टर नमित मेहता ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री शनिवार सुबह 9.25 बजे विशेष विमान द्वारा जयपुर से प्रस्थान कर सुबह 10.10 बजे महाराणा प्रताप एयरपोर्ट डबोक पहुंचेंगें। यहां से सुबह 10.15 बजे हेलीकॉप्टर द्वारा बांसवाड़ा के लिए प्रस्थान करेंगे। जिला कलक्टर ने मुख्यमंत्री के यात्रा कार्यक्रम के मद्देनजर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

समाचार भेजने के लिए हमारी मेल आई-डी पर संपर्क करें -
desk24newsupdate@gmail.com

पंचायत–निकाय चुनावः काम नहीं आया लोढ़ा का 'संयम', सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप से इनकार, राजस्थान सरकार 15 अप्रैल तक करा सकेगी चुनाव

24 न्यूज अपडेट

नई दिल्ली / जयपुर। राजस्थान में पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनावों को लेकर चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही राज्य सरकार को प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव 15 अप्रैल 2026 तक कराने का मार्ग साफ हो गया है। यह आदेश जस्टिस जॉयमाला बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने पूर्व विधायक संयम लोढ़ा द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP) पर सुनवाई के दौरान दिया। याचिका में राजस्थान हाईकोर्ट के 14 नवंबर 2025 के आदेश को चुनौती दी गई थी।

हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया था कि संविधान के अनुसार शहरी निकायों और पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद समय पर चुनाव कराना अनिवार्य है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि परिसीमन को चुनाव टालने का आधार नहीं बनाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए संकेत दिया कि हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित समय-सीमा और दिशा-निर्देशों में कोई ऐसी कानूनी त्रुटि नहीं है, जो सर्वोच्च न्यायालय के दखल को आवश्यक बनाए।

सरकार ने जताई समय पर चुनाव कराने की प्रतिबद्धता

राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज और अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने अदालत को बताया कि सरकार हाईकोर्ट द्वारा तय की गई समय-सीमा के भीतर पंचायत और निकाय चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है और इसकी प्रक्रिया प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश स्थानीय स्वशासन से जुड़े संवैधानिक और वैधानिक ढांचे के अनुरूप तथा संतुलित है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप राज्यव्यापी परिसीमन प्रक्रिया को बाधित कर सकता है, जिससे वार्ड सीमाओं, मतदाता सूचियों और आरक्षण रोस्टर को लेकर असमंजस की स्थिति पैदा होगी।

15 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने के निर्देश

उल्लेखनीय है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने 14 नवंबर 2025 को लगभग 439 याचिकाओं पर एक साथ फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव 15 अप्रैल 2026 तक कराए जाएं। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया था कि सरकार 31 दिसंबर तक परिसीमन की प्रक्रिया पूरी करे, और एक बार परिसीमन का अंतिम नोटिफिकेशन जारी हो जाने के बाद उसे अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

SOG ने जयपुर से असिस्टेंट फायर ऑफिसर को दबोचा, फर्जी डिग्री, तीन साल से कर रही थी नौकरी

24 न्यूज अपडेट

जयपुर। राजस्थान में सरकारी भर्तियों की शुचिता पर सवाल खड़े करने वाले एक बड़े फर्जीवाड़े का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने पर्दाफाश किया है। जयपुर के मालवीय नगर जोन में तैनात असिस्टेंट फायर ऑफिसर को गुरुवार देर शाम SOG ने गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि महिला अधिकारी ने फर्जी और नियमविरुद्ध शैक्षणिक दस्तावेजों के सहारे सरकारी नौकरी हासिल की और करीब तीन वर्षों तक पद पर बनी रही।

ADG (SOG) विशाल बंसल ने बताया कि आरोपी सोबिया सैयद को फायर भर्ती परीक्षा-2021 से जुड़े फर्जीवाड़े में गिरफ्तार किया गया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि लिखित परीक्षा के बाद फिजिकल और प्रैक्टिकल टेस्ट में आरोपी को उसके वास्तविक प्रदर्शन से कहीं अधिक अंक दिए गए। यहीं से SOG को पूरे चयन पर संदेह हुआ और जांच का दायरा बढ़ाया गया।

एक ही सत्र में कई डिग्रियां, सिस्टम को किया गुमराह

DIG (SOG) परिस देशमुख के अनुसार जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। सोबिया सैयद ने एक ही शैक्षणिक सत्र में अलग-अलग संस्थानों से कई डिग्री और डिप्लोमा प्राप्त किए। आरोपी ने राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी, कोटा से नियमित मोड में बी.टेक की डिग्री हासिल की। इसी दौरान महाराष्ट्र के नागपुर स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग (NIFSE) से फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग का एक वर्षीय डिप्लोमा भी नियमित मोड में प्राप्त किया। यहीं मामला नहीं रुका। NIFSE नागपुर से लिखित परीक्षा का परिणाम आने के बाद आरोपी ने दोबारा 'असिस्टेंट फायर ऑफिसर' का डिप्लोमा प्राप्त किया। इसके साथ ही उसी शैक्षणिक सत्र में झुंझुनूं स्थित सिंघानिया यूनिवर्सिटी से भी 'असिस्टेंट फायर ऑफिसर' का डिप्लोमा हासिल किया गया। दोनों संस्थानों के बीच करीब 900 किलोमीटर की दूरी है, जिससे एक साथ नियमित अध्ययन पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

फर्जी दस्तावेजों से मिली सरकारी पोस्टिंग

SOG की जांच में सामने आया कि इन डिप्लोमा प्रमाण पत्रों के आधार पर आरोपी ने कर्मचारी चयन बोर्ड और स्वायत्त शासन विभाग को गुमराह किया। इसी फर्जीवाड़े के सहारे साल 2022 में उसे असिस्टेंट फायर ऑफिसर के पद पर नियुक्ति मिल गई। तब से वह जयपुर के मालवीय नगर जोन में पदस्थ थी।

पूछताछ जारी, और खुलासों की संभावना

SOG ने आरोपी महिला अधिकारी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। जांच एजेंसी यह भी पड़ताल कर रही है कि भर्ती प्रक्रिया में किसी अन्य स्तर पर मिलीभगत तो नहीं हुई और फिजिकल-प्रैक्टिकल परीक्षा में अधिक अंक कैसे दिए गए। अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ के दौरान और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं।

विधायक कमीशन कांड : सदाचार कमेटी से जिसने जितना टाइम मांगा, उतना दिया, 7, 10 और 15 दिन में पेश करने होंगे सबूत

24 न्यूज अपडेट

जयपुर। विधायक फंड में कमीशन मांगने के सनसनीखेज आरोपों पर विधानसभा की सदाचार कमेटी ने जांच को निर्णायक मोड़ देते हुए तीनों विधायकों को स्पष्ट समय-सीमा दे दी है। शुक्रवार को हुई लंबी पूछताछ के बाद कमेटी ने साफ कर दिया कि अब आरोप–प्रत्यारोप नहीं, बल्कि निर्धारित समय में ठोस सबूत ही तय करेंगे आगे की कार्रवाई।

सभापति कैलाश वर्मा की अध्यक्षता वाली सदाचार कमेटी ने सबसे पहले बयाना से निर्दलीय विधायक ऋतु बनावत, फिर हिंडौन से कांग्रेस विधायक अनीता जाटव और अंत में खींवसर से भाजपा विधायक रेवंतराम डांगा से वन-टू-वन पूछताछ की। तीनों से सीधा सवाल किया गया—क्या आपने विधायक फंड से काम दिलाने के बदले कमीशन मांगा? तीनों विधायकों ने आरोपों से इनकार किया, लेकिन जब कमेटी ने सबूत मांगे तो सभी ने अलग-अलग समय की मांग रखी।

कमेटी ने तय किया साफ कैलेंडर कमेटी ने विधायकों की मांग स्वीकार करते हुए जांच का स्पष्ट कैलेंडर तय कर दिया—

अनीता जाटव को 7 दिन
ऋतु बनावत को 10 दिन
रेवंतराम डांगा को 15 दिन

इन तय तारीखों के बाद तीनों को दोबारा बुलाकर विस्तार से पूछताछ की जाएगी। रेवंतराम डांगा ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कहा कि वह सभी जवाब अगली पेशी में देंगे। पूरा मामला स्टिंग ऑपरेशन के बाद सदन तक पहुंचा। स्टिंग में तीनों विधायक अपने विधायक फंड से काम दिलाने के बदले डील करते कैमरे में कैद हुए थे।

रेवंतराम डांगा पर 50 लाख के काम के बदले 40% कमीशन मांगने का आरोप है।

ऋतु बनावत के मामले में उनके पति की डील सामने आई।

अनीता जाटव पर रिपोर्टर से 50 हजार रुपए टोकन मनी लेने का आरोप है।

सभापति कैलाश वर्मा ने कहा कि कमेटी स्वतंत्र और पावरफुल है। समय पूरा होते ही विधायकों को फिर नोटिस देकर बुलाया जाएगा। जरूरत पड़ी तो ऋतु बनावत के पति को भी तलब किया जा सकता है। कमेटी स्टिंग करने वाले पत्रकार से भी पूछताछ करेगी और उसके बाद तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार कर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को सौंपी जाएगी।

खाकी का साहसः धधकते बेसमेंट में काल को मात दे आए कांस्टेबल सतनाम सिंह, बचाई 5 जिंदगियां

24 न्यूज अपडेट

जयपुर 19 दिसम्बर। राजस्थान पुलिस के एक जांबाज सिपाही ने अपनी जान जोखिम में डालकर मौत के मुंह से पांच युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। कस्बे के हीरो चौक स्थित यदुवंशी कॉलोनी के जय गेस्ट हाउस में बुधवार रात हुए भीषण अग्निकांड में कांस्टेबल सतनाम सिंह एक देवदूत बनकर सामने आए। उनकी इस वीरता पर महानिदेशक पुलिस श्री राजीव शर्मा ने उन्हें डीजीपी डिस्क से सम्मानित करने की घोषणा की है।

आधी रात को मफलर बांधकर आग के तांडव में कूदे सतनाम बुधवार रात जब गेस्ट हाउस के बेसमेंट में अचानक आग लगी तो वहां ठहरे छह युवकों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। भारी धुएं और लपटों के बीच चीख-पुकार मच गई। उसी समय क्षेत्र में रात्रि गश्त कर रहे कांस्टेबल सतनाम सिंह (नंबर 931) को सूचना मिली। बिना एक पल गंवाए सतनाम मौके पर पहुंचे।

बेसमेंट में इतना घना धुआं था कि सांस लेना नामुमकिन था, लेकिन सतनाम ने सूझबूझ दिखाई और अपने मुंह पर अपना मफलर बांधकर आग की लपटों के बीच घुस गए। दम घोंटू धुएं के बीच सतनाम ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए बेसमेंट में फंसे सभी छह युवकों को बाहर निकाला और तुरंत उपचार के लिए मनोहर हॉस्पिटल रवाना किया। हालांकि, इस हादसे की भयावहता के कारण एक युवक को नहीं बचाया जा सका, लेकिन सतनाम के त्वरित प्रयासों से पांच युवकों की जान बच गई।

डीजीपी राजीव शर्मा ने की डीजीपी डिस्क देने की घोषणा कांस्टेबल सतनाम सिंह की इस वीरता की गूंज राजधानी जयपुर तक पहुंची। महानिदेशक पुलिस श्री राजीव शर्मा ने घटना का संज्ञान लेते हुए कांस्टेबल के कार्य की सराहना की और उनकी हौसला-अफजाई के लिए त्वरित निर्णय लेते हुए उन्हें डीजीपी डिस्क प्रदान करने की घोषणा की।

डीजीपी श्री शर्मा ने कांस्टेबल की सराहना करते हुए कहा कि सतनाम सिंह ने अपनी जान की परवाह किए बिना जिस तरह आमजन की रक्षा की, वह पुलिस विभाग के प्रत्येक जवान के लिए प्रेरणा है। उनकी सूझबूझ और बहादुरी ने खाकी का मान बढ़ाया है।

रोडवेज की व्यवस्था सुधारने की उठी मांग, ग्राहक पंचायत ने सौंपा ज्ञापन

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत संगठन द्वारा ग्राहक पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत रोडवेज बस स्टैंड की अव्यवस्थाओं को लेकर रोडवेज के मुख्य प्रबंधक हेमन्त शर्मा को ज्ञापन सौंपा गया। ग्राहक पंचायत संगठन के प्रांत संगठन मंत्री राकेश पालीवाल एवं जिला अध्यक्ष शिवकुमार शर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने यात्रियों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं की ओर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया।

ग्राहक पंचायत के जिला मंत्री नारायण पंचोली ने बताया कि ज्ञापन में मुख्य बस स्टैंड उदियापोल पर सभी टिकट खिड़कियां बंद होने से यात्रियों को हो रही भारी परेशानी का उल्लेख करते हुए इन्हें पुनः प्रारंभ करने की मांग की गई। इसके साथ ही उदयपुर से निंबाहेड़ा, नीमच, बड़ी सादड़ी एवं केलवाड़ा रूट पर राजस्थान रोडवेज की बसें नियमित रूप से चलाने की मांग रखी गई। ज्ञापन में बस स्टैंड पर पार्किंग शुल्क एवं रात्रि शुल्क मनमाने ढंग से वसूल किए जाने पर आपत्ति जताते हुए नियमानुसार वसूली सुनिश्चित करने तथा बस किराया शुल्क को स्पष्ट रूप से सूचना बोर्ड पर प्रदर्शित करने का आग्रह भी किया गया।

इस अवसर पर मुख्य प्रबंधक हेमन्त शर्मा ने स्टाफ की कमी के चलते टिकट खिड़कियां बंद करने की मजबूरी बताई और आश्वासन दिया कि एक माह के भीतर नई भर्ती होने पर यात्रियों की सुविधा के लिए टिकट खिड़कियां पुनः खोल दी जाएंगी। साथ ही संबंधित रूटों पर बसों के संचालन एवं पार्किंग शुल्क को नियमानुसार वसूलने के निर्देश दिए जाने का भरोसा भी प्रतिनिधिमंडल को दिलाया। प्रतिनिधिमंडल में करण सिंह कटारिया, रमेश जोशी, फतेहलाल पारिक, मंजू भावसार, अनिल टांक, जयप्रकाश भावसार सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

अजमेर में वकीलों ने PWD अधिकारी को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा

24 न्यूज अपडेट

अजमेर। जिस जगह पर कानून की भाषा में न्याय तय होता है, उसी जिला न्यायालय के बाहर सोमवार को हालात कुछ समय के लिए नियंत्रण से बाहर होते दिखे। जयपुर रोड पर नए जिला न्यायालय भवन के सामने स्पीड ब्रेकर निर्माण की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने सड़क के दोनों ओर आवागमन रोक दिया, जिससे शहर की एक प्रमुख सड़क करीब ढाई घंटे तक ठप रही। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सिविल लाइन थाना पुलिस, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और बाद में पीडब्ल्यूडी (लोक निर्माण विभाग) के एक अधिकारी को मौके पर बुलाया गया, ताकि गतिरोध को बातचीत से सुलझाया जा सके।

बातचीत से पहले बढ़ा तनाव

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पीडब्ल्यूडी अधिकारी के मौके पर पहुंचने के बाद बातचीत के दौरान माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। कुछ अधिवक्ता आक्रोशित हो गए और स्थिति हाथ से निकलती नजर आई। इसी दौरान अधिकारी को लेकर हंगामे और हाथापाई की स्थिति बन गई। पुलिस ने तत्काल हस्तक्षेप करते हुए अधिकारी को अधिवक्ताओं के बीच से निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। घटना पुलिस की मौजूदगी में हुई, जिसके चलते हालात और संवेदनशील हो गए।

वरिष्ठ अधिकारियों ने संभाला मोर्चा

पीडब्ल्यूडी अधिकारी के साथ कथित दुर्व्यवहार की सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी सिटी हिमांशु जांगिड़ और प्रशिक्षु आईपीएस अजय सिंह मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों से चर्चा कर स्थिति को शांत करने का प्रयास किया। लगातार संवाद और आश्वासन के बाद करीब ढाई घंटे बाद जयपुर रोड पर यातायात बहाल हो सका।

क्या है अधिवक्ताओं की मुख्य मांग

जिला बार एसोसिएशन के सचिव रूपेंद्र परिहार के अनुसार, जिला न्यायालय का नया भवन बनकर तैयार हो चुका है और वहां नियमित न्यायिक कार्य प्रारंभ हो गया है। हालांकि, अधिवक्ताओं के बैठने की पर्याप्त व्यवस्था अब भी पुराने भवन में है। इस कारण अधिवक्ताओं और हजारों पक्षकारों को रोजाना जयपुर रोड पार कर नए कोर्ट भवन तक जाना पड़ता है, जो एक हाई-स्पीड रोड है। पूर्व में कई अधिवक्ता और वादकारी सड़क पार करते समय दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। सोमवार को भी एक अधिवक्ता के वाहन की चपेट में आने की सूचना के बाद विरोध तेज हुआ।

दो घंटे में समाधान का आश्वासन

बार एसोसिएशन के अनुसार, प्रशासन की ओर से दो घंटे के भीतर स्पीड ब्रेकर निर्माण का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद प्रदर्शन समाप्त कर सड़क खोल दी गई। पीडब्ल्यूडी अधिकारी से कथित मारपीट के आरोपों पर सचिव रूपेंद्र परिहार ने कहा कि किसी अधिवक्ता ने अधिकारी पर हाथ नहीं उठाया। उनका दावा है कि अधिकारी द्वारा बार अध्यक्ष से कथित रूप से अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, जिसके बाद स्थिति बिगड़ी और पुलिस द्वारा अधिकारी को हटाने के दौरान गलतफहमी पैदा हुई।

कार्यक्रमों का पुनः प्रसारण करने के लिए रिले स्टेशन स्थापित किए : : सांसद

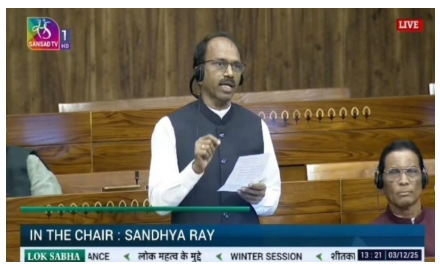

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। आकाशवाणी स्टेशनों द्वारा निर्मित कार्यक्रमों का पुनः प्रसारण करने के लिए प्रसार भारती के रिले स्टेशन पूरे देश में स्थापित किए गए हैं। इससे तकनीकी और मानव संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित हो रहा है और सार्वजनिक प्रसारण की व्यापक जनसंपर्क क्षमता भी बढ रही है, जिससे कार्यक्रम की गुणवता बनी रहती है। सांसद डॉ. मन्ना लाल रावत द्वारा संसद में पूछे गए प्रश्न पर सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने यह जानकारी दी। सांसद डॉ रावत ने वर्तमान में देश भर में स्थापित आकाशवाणी केन्द्र, मूल कार्यक्रम का निर्माण और प्रसारण करने वाले आकाशवाणी केन्द्र, कई आकाशवाणी केंद्रों द्वारा मूल कार्यक्रम प्रसारित करने के बजाय अन्य आकाशवाणी केंद्रों के कार्यक्रमों को रिले करने तथा उदयपुर जिलों में पांच वर्ष पूर्व स्थापित आकाशवाणी केंद्रों से अन्य आकाशवाणी केंद्रों के कार्यक्रमों को रिले करने के कारण को लेकर प्रश्न किए थे। जवाब में सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने बताया कि वर्तमान में, आकाशवाणी के 591 प्रसारण स्टेशन देशभर में कार्यरत हैं। इनमें से 230 स्टेशनों में मूल कार्यक्रमों के निर्माण और प्रसारण के लिए स्टूडियो सुविधा उपलब्ध है। शेष 361 स्टेशन प्रसारण की पहुंच बढ़ाने के लिए अन्य आकाशवाणी केंद्रों के कार्यक्रमों की रिले करते हैं। भीलवाड़ा में स्थित एक 100 वाट एफएम रिले स्टेशन (जिसे 28.04.2023 को रिले स्टेशन के रूप में चालू किया गया था) विविध भारती सेवा का प्रसारण करता है। आकाशवाणी उदयपुर के पास कार्यक्रमों के निर्माण और प्रसारण के लिए स्टूडियो की सुविधा उपलब्ध है। यह विविध भारती सेवा (एफएम) पर स्थानीय स्तर पर कार्यक्रमों का निर्माण करता है।

पहाड़ कटे, आयड़ नदी की हुई हत्या-सब चुप थे।

अरावली को बचाने अब सब जुटे हैं!!!

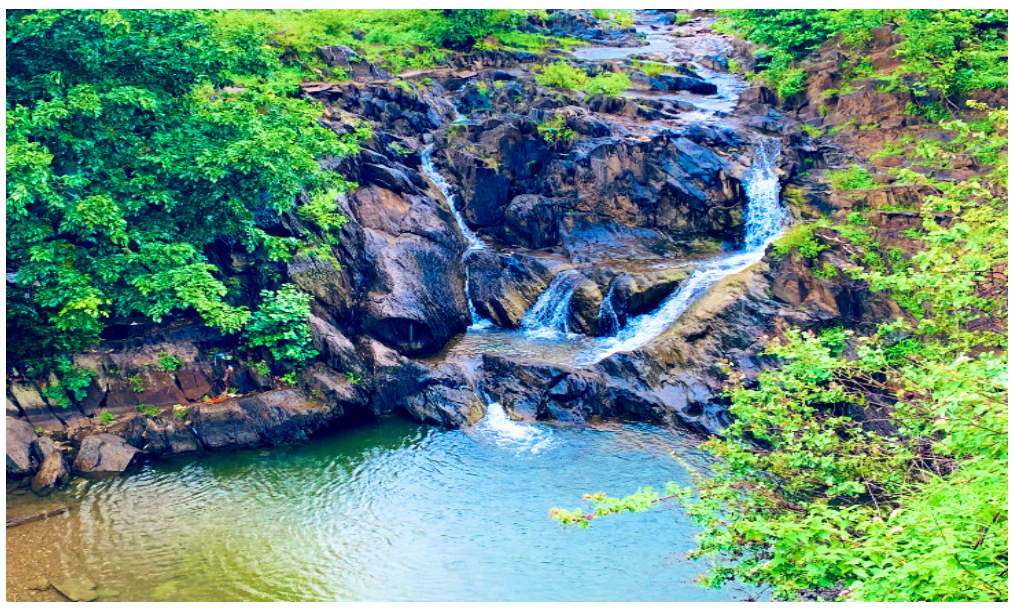

24 न्यूज अपडेट

अरावली के पहाड़ उदयपुर की लाइफ लाइन है।

आज यही सांस की डोर सिस्टम के हाथों काटी जा रही है। यह सुनियोजित कत्ले आम है। हथौड़ा भू-माफिया का है, ढाल अफसरों की है और मौन समर्थन नेताओं का। पहाड़ दिन में नक्शों में रहते हैं और रात में ट्रकों में भरकर शहर से बाहर निकल जाते हैं। प्रशासन कहता है— 'हमें जानकारी नहीं।' नेता कहते हैं— 'यह हमारे कार्यकाल का मामला नहीं।' और माफिया वह पहाड़ गिनता नहीं, वह रेट तय करता है। तीनों पैसा खाकर मस्त हो जाते हैं। 25–30 साल में उदयपुर में यही सब चल रहा है। नक्शे बदल गए, पहाड़ कटे, झीलें सिकुड़ीं, नदी को नाला बना दिया, भूजल गिरा— लेकिन एक चीज़ नहीं बदली सिस्टम की मिलीभगत। और जनता, हमेशा सोई रही, विरोध की छोटी मोटी आवाजें घोंचेबाज कह कर दबा दी गई। आप पूछेंगे कि किसने दबाई?? तो जवाब है उन्हीं नेताओं ने जो आज महान बनकर घूम रहे हैं? फीते काटते फिर रहे हैं?? उन्हीं अफसरों ने जो आज भाषण देते फिर रहे हैं? याने पहाड़ों व नदियों के हत्यारे हमारे बीच घूम रहे हैं और हम हैं कि अब विरोध की आवाज बुलंद करके सोच रहे हैं कि पर्यावरण बचा लेंगे।

जब कोर्ट सवाल पूछता है तो यही नेता अफसर ग्रीन कवर, रिपोर्ट और हलफनामे लेकर खड़े हो जाते हैं। और जैसे ही फाइल बंद होती है— डंपर फिर चल पड़ते हैं। जैसा कि आयड़ में चल रहे हैं। बेशर्मी की हद तक।

आज अरावली बचाने की बात उसी कलेक्टरेट पर की जा रही है जहां से अवैध कटाई की फाइलें सालों से 'अंडर प्रोसेस' हैं। लोग कह रहे हैं— 'पहाड़ बचाओ।' लेकिन सवाल ये है— किससे? उसी प्रशासन से जिसके संरक्षण में पहाड़ों पर ब्लास्ट किए गए? उन्हीं नेताओं से जिन्होंने मंचों से पर्यावरण दिवस मनाया और पीछे से खनन की फाइलें बढ़ाईं?

अरावली किसी माफिया से नहीं हार रही। वह हार रही है व्यवस्था की चुप्पी से। अगर आज यह गठजोड़ नहीं टूटा,तो आने वाली पीढ़ियां अरावली को केवल किताबों में पढ़ेंगी और बच्चे कहेंगे— लानत है उस पीढ़ी पर जिसने अरावली को बचाने के लिए कुछ नहीं किया, मौनी बाबा बनकर सब देखते रहे। आज उदयपुर की सड़कों पर लोग सच बोल रहे हैं। मगर नंग सच ये है कि अरावली के हत्यारों के इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक वैसा ही जैसा आयड़ की हत्या से नहीं पड़ रहा है।

हाथीपोल में अस्थाई पुलिस चौकी, अम्बेरी में ट्रैफिक बूथ शुरू

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर शहर में कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने तथा आमजन व पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में पुलिस प्रशासन ने एक और कदम बढ़ाया है। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने शुक्रवार को हाथीपोल बाजार में अस्थाई पुलिस चौकी और अम्बेरी पुलिया के नीचे यातायात बूथ/पुलिस सहायता केंद्र का शुभारंभ किया। पन्नाधाय मार्ग स्थित हाथीपोल बाजार में फिनोवा कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से स्थापित अस्थाई पुलिस चौकी का उद्देश्य संवेदनशील क्षेत्र में पुलिस की मौजूदगी बढ़ाना, त्वरित सहायता उपलब्ध कराना और अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाना है। उद्घाटन अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) उमेश ओझा, वृताधिकारी नगर पश्चिम राजेश यादव, यातायात उप अधीक्षक अशोक आंजना, थानाधिकारी हाथीपोल राजूदेवी राज सहित पुलिसकर्मी और व्यापार मंडल के प्रतिनिधि मौजूद रहे। एसपी योगेश गोयल ने बताया कि शहर में बढ़ते पर्यटन को देखते हुए पुलिस ऐसे नवाचार कर रही है, जिससे पर्यटकों को सुरक्षित और भरोसेमंद माहौल मिल सके। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए यह चौकी स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों दोनों के लिए मददगार साबित होगी। उन्होंने आसपास के व्यापारियों से भी पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं और सहयोग देने की अपील की। हाथीपोल बाजार के व्यापारियों ने पुलिस चौकी की स्थापना का स्वागत करते हुए पुलिस अधिकारियों का सम्मान किया और इसे क्षेत्र के लिए सकारात्मक पहल बताया। इसी क्रम में अम्बेरी पुलिया के नीचे यातायात बूथ/पुलिस सहायता केंद्र का भी शुभारंभ किया गया। इस बूथ के जरिए यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के साथ-साथ दुर्घटना या आपात स्थिति में आमजन को तत्काल मदद उपलब्ध कराई जाएगी।

चार्टर्ड अकाउंटेंटस की दो दिवसीय नेशनल कांफ्रेंस 'प्रज्ञान' का शुभारम्भ आज

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर, 19 दिसम्बर। बड़े बड़े उद्योगपतियों से लेकर आमजन के आमद खर्च का हिसाब रखने वालों का शनिवार से दो दिन तक उदयपुर में मजमा लगा रहेगा। उदयपुर संभाग की सबसे बड़ी आयोजित होने वाली चार्टर्ड अकाउंटेंटस की दो दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस का आग़ाज़ शनिवार को सॉलिटेयर गार्डन स्थित सभागार में होगा। कॉन्फ्रेंस लीड कन्वीनर सीए केशव मालू व कन्वीनर सीए आशीष ओस्तवाल ने बताया कि इंस्टीट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आफ़ इंडिया की प्रोफेशनल डेवलपमेंट कमेटी के तत्वावधान में होने वाली इस कांफ्रेंस में देश भर के लगभग 1500 से ज़्यादा सीए भाग लेंगे। कांफ्रेंस के टाइटल स्पॉन्सर वेदांता ग्रुप की हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है।

इंस्टिट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की उदयपुर शाखा के अध्यक्ष सीए राहुल माहेश्वरी ने बताया कि सम्मानित अतिथि के रूप में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के सीएफओ सीए संदीप मोदी व सिक्योर मीटर्स लिमिटेड के चेयरमैन संजय सिंघल उपस्थित रहेंगे। माहेश्वरी ने बताया कि दो दिवसीय आयोजन को लेकर शुक्रवार को सभी सदस्यों द्वारा अंतिम रूप दिया गया।

मीडिया कमेटी चेयरमैन सीए हितेष भदादा ने बताया कि प्रथम दिन 20 दिसम्बर को तीन तकनीकी सत्र होंगे । पहले सत्र में विषय विशेषज्ञ सीए अशोक बत्रा जीएसटी एक्ट में डिस्प्यूट्स को कैसे हैंडल करना विषय पर चर्चा करेंगे।

द्वितीय सत्र में सीए गौरव अरोड़ा प्रैक्टिस में सीए व्यवसायिक विकास के नए अवसरों द्वारा आमदनी बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। तृतीय सत्र में कैपिटल मार्केट में सीए के अवसरों पर विजय मंत्री व आशीष सोमैया पैनल डिस्कशन करेंगे। शाम को कांफ्रेंस के सदस्यों व परिवार जनों के लिए सांस्कृतिक संध्या का आयोजन सॉलिटेयर गार्डन में ही होगा।

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष नंदा कांफ्रेंस में सीए सदस्यों को सम्बोधित करेंगे

उदयपुर शाखा कोषाध्यक्ष व मीडिया को-चेयरमैन सीए सौरभ गोलछा ने बताया कि कांफ्रेंस के दूसरे दिन 21 दिसम्बर को इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीए चरनजोत सिंह नंदा कांफ्रेंस में सीए सदस्यों को सम्बोधित करेंगे। प्रथम सत्र में कंपनी एक्ट के तहत रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन और शेड्यूल 3 पर सीए प्रमोद जैन चर्चा करेंगे । दूसरे सत्र में आज के युग के सबसे महत्वपूर्ण विषय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सीए जय छेड़ा सदस्यों का ज्ञान वर्धन करेंगे । आखरी सत्र में काला धन, सर्च व सीजर पर सीए टी.पी.ओस्तवाल, सीए प्रमोद जैन व सीए हिमांशु गोयल पैनल डिस्कशन करेंगे ।

शाखा उपाध्यक्ष सीए चिराग धर्मावत ने बताया की सेंट्रल कौंसिल मेंबर सीए रोहित रुवटीया अग्रवाल, सीए अभय छाजेड, सीए अनुज गोयल, सीए ज्ञान प्रकाश मिश्रा, सीए सतीश गुप्ता व सीए पंकज शाह आदि उदयपुर पहुँच गए।

शाखा सचिव सीए धर्मेन्द्र कोठारी ने बताया उद्घाटन सत्र से पहले डेलीगेट्स का रजिस्ट्रेशन होगा व किट वितरण किया जाएगा।

भूपालपुरा में एमडीएमए पर पुलिस का प्रहार, डीएसटी–थाना टीम ने दो तस्करों को दबोचा

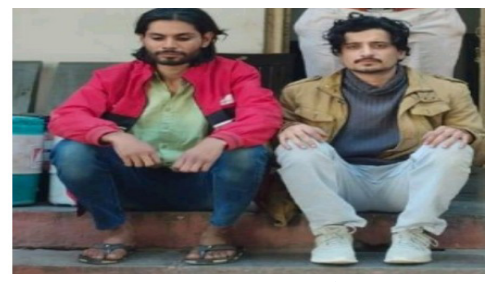

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चल रहे विशेष अभियान के तहत डीएसटी और पुलिस थाना भूपालपुरा की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई में एमडीएमए (ड्रग्स) के साथ दो आरोपियों को अलग-अलग स्थानों से गिरफ्तार किया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) उमेश ओझा और वृताधिकारी नगर पूर्व सूर्यवीर सिंह के सुपरविजन में थानाधिकारी भूपालपुरा कानाराम सिरवी के नेतृत्व में टीम ने पहली कार्रवाई शास्त्री सर्कल के पास की। यहां से दानिश उर्फ डिके पुत्र अब्दुलुद्दीन, निवासी चुड़ीघरों का मोहल्ला, मुखर्जी चौक (थाना धानमंडी) को 5.97 ग्राम अवैध मादक पदार्थ एमडीएमए के साथ गिरफ्तार किया गया। इसके बाद पुलिस ने दूसरी कार्रवाई में आयड़ महासतिया के बाहर से मोहम्मद साहिल पुत्र मोहम्मद शराफत, निवासी गली नंबर-01, लोहार कॉलोनी, आयड़ (थाना भूपालपुरा) को 1.75 ग्राम एमडीएमए के साथ दबोच लिया। दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत अलग-अलग प्रकरण दर्ज कर लिए गए हैं और मादक पदार्थ की सप्लाई चेन को लेकर आगे की गहन जांच जारी है। इस कार्रवाई में थानाधिकारी कानाराम सिरवी, हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र सिंह, कांस्टेबल देवीलाल, कांस्टेबल वीरेंद्र सिंह सहित जिला स्पेशल टीम की अहम भूमिका रही। पुलिस का कहना है कि शहर में नशे के कारोबार पर सख्ती लगातार जारी रहेगी।

निर्माण कार्य पर उपकर अनिवार्य, उदयपुर में सख्तीः सैकड़ों भवन मालिकों को नोटिस, नहीं भरा तो कुर्की तय

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर, 19 दिसंबर। राज्य में लागू भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (श्रमिक) कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के तहत अब निर्माण कार्य पर उपकर वसूली को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। उदयपुर संभाग में श्रम विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सैकड़ों भवन मालिकों और नियोजकों को नोटिस जारी किए हैं। तय समय में उपकर जमा नहीं कराने पर कुर्की तक की कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त संकेत मोदी ने बताया कि 27 जुलाई 2009 के बाद निर्मित सरकारी, वाणिज्यिक और निजी (आवासीय) भवनों व निर्माण कार्यों की कुल लागत पर 1 प्रतिशत उपकर (सेस) देय है। राजस्थान में किसी भी वर्ग या निर्माण कार्य को उपकर से छूट नहीं दी गई है। केवल 10 लाख रुपये से कम लागत वाले आवासीय भवनों को इससे बाहर रखा गया है, जबकि इससे अधिक लागत वाले आवासीय और सभी वाणिज्यिक भवन उपकर के दायरे में आते हैं। अधिनियम के अनुसार भवन निर्माण शुरू करने के 30 दिन के भीतर श्रम विभाग को सूचना देना और निर्माण पूर्ण होने या उपकर निर्धारण के 30 दिन के भीतर उपकर राशि जमा कराना अनिवार्य है। यदि निर्माण कार्य एक वर्ष से अधिक समय तक चलता है तो हर वर्ष उपकर जमा करना होगा। नियोजक चाहें तो अनुमानित लागत के आधार पर अग्रिम उपकर भी जमा करा सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक उदयपुर संभाग में 678 भवन मालिकों और नियोजकों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। इनमें से 22 प्रकरण वसूली की प्रक्रिया में हैं, जबकि 10 मामलों में एकतरफा कार्रवाई करते हुए उपकर निर्धारण आदेश जारी किए गए हैं। तय समय में राशि जमा नहीं होने पर ये प्रकरण जिला कलेक्टर को वसूली के लिए भेजे जाएंगे। श्रम विभाग ने स्पष्ट किया है कि नोटिस के बाद भी यदि उपकर जमा नहीं कराया गया तो विभाग स्वयं निर्माण लागत का आकलन कर एकपक्षीय आदेश जारी करेगा। उपकर समय पर जमा नहीं होने की स्थिति में 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज और आदेश के बाद भुगतान नहीं करने पर 100 प्रतिशत तक पेनल्टी लगाने का प्रावधान है। ब्याज और पेनल्टी सहित वसूली की कार्रवाई की जाएगी। श्रम आयुक्त के निर्देश पर विभाग ने अधिक से अधिक भवन नियोजकों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने भवन मालिकों से अपील की है कि वे दस्तावेजों के साथ समय रहते उपकर जमा कराएं, ताकि कड़ी कार्रवाई से बचा जा सके।

जे.के.सीमेंट वर्क्स, निम्बाहेड़ा ने ग्राम मुरलिया में मिशन लाइफ जागरूकता अभियान आयोजित किया !

24 न्यूज अपडेट

निम्बाहेड़ा।जे.के. सीमेंट वर्क्स, निम्बाहेड़ा द्वारा भारत सरकार की मिशन लाइफ (लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट) पहल के अंतर्गत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, ग्राम मुरलिया में पर्यावरण संरक्षण एवं सतत जीवनशैली को प्रोत्साहित करने हेतु एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल चित्तौड़गढ़ से रवि कुमार मीणा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर विद्यालय प्राचार्य श्रीमती किरण शर्मा तथा जे.के. सीमेंट से पर्यावरण प्रमुख चंद्रकांत तिवारी, सीएसआर विभाग से राहुल सिंह तथा पर्यावरण विभाग से रवि पाटीदार ने कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विद्यालय परिसर में स्वच्छता अभियान, पौधारोपण कार्यक्रम तथा प्लास्टिक मुक्त परिसर को बढ़ावा देने हेतु विशेष गतिविधियाँ भी आयोजित की गईं। विद्यार्थियों ने पर्यावरण संरक्षण से जुड़े संदेशों वाले पोस्टर एवं नारों के माध्यम से पूरे गाँव में रैली निकालकर जनजागरूकता फैलाई तथा कार्यक्रम को सफल बनाने में सक्रिय भागीदारी निभाई। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को पर्यावरण संरक्षण, जल एवं ऊर्जा की बचत, कचरा प्रबंधन, प्लास्टिक मुक्त जीवनशैली तथा पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार व्यवहार अपनाने के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर मिशन लाइफ पर आधारित जागरूकता सत्र, पर्यावरण क्विज प्रतियोगिता, चित्रकला एवं पेंटिंग प्रतियोगिता तथा नारा लेखन गतिविधि का आयोजन किया गया।

प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पर्यावरण- अनुकूल उपहार प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के समापन पर विद्यार्थियों को जल संरक्षण, ऊर्जा बचत, कचरे में कमी लाने तथा सिंगल-यूज़ प्लास्टिक से बचने की शपथ दिलाई गई।

अरावली पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ माँ शारदा आर्य समिति की ओर से प्रदर्शन!!

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर में आज माँ शारदा आर्य समिति की ओर से जिला कलेक्टर को एक अहम ज्ञापन सौंपा गया। आर्य समाज उदयपुर की सहयोगी इस संस्था ने जनहित, पर्यावरण संरक्षण और संवैधानिक अधिकारों का हवाला देते हुए अरावली की बरानी पहाड़ियों से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पुनर्विचार की मांग की है। संस्था का कहना है कि अरावली पर्वत श्रृंखला सिर्फ पहाड़ नहीं, बल्कि पर्यावरण संतुलन, जल संरक्षण और जैव विविधता की जीवनरेखा है। इन पहाड़ियों में किसी भी तरह का हस्तक्षेप आने वाली पीढ़ियों के मौलिक अधिकारों पर सीधा हमला होगा। माँ शारदा आर्य समिति ने राज्य और केंद्र सरकार से अरावली संरक्षण के लिए ठोस और दीर्घकालिक नीति बनाने की मांग की है, ताकि प्राकृतिक विरासत को बचाया जा सके।

24 न्यूज़ अपडेट- डिजिटल संस्करण स्वामित्व एवं प्रसारण ग्रुप के लिए करण सिंह देवड़ा द्वारा ई-न्यूज पेपर के फारमेट में प्रसारित प्रधान सम्पादक - सुशील जैन फोन .88520 73787, desk24newsupdate@gmail.com सर्वविवादों का न्याय क्षेत्र उदयपुर रहेगा ।